



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-02082023-247771
CG-WB-E-02082023-247771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]
No. 534]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (संसद के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोलकाता, 1 अगस्त, 2023

सीडब्ल्यूआर(1)/2023.—लागत और कार्य लेखाकार विनियम, 1959 में और अधिक संशोधन करने के लिए विनियमावली के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे करने के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद प्रस्ताव करती है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी हितधारकों की सूचना के लिए लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा, जब भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें ये प्रारूप विनियम प्रकाशित किए जाएं, जनता को उपलब्ध करा दिए जाएं।

उपर्युक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, सीएमए भवन, 12, सडर स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016 को संबोधित निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद द्वारा विचारार्थ उसे भेज सकता है।

निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व उपर्युक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों को लागत एवं कार्य लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम, 1959 में
 - (i) मूल विनियम के विनियम 1 के, उप-विनियम (1) में, "लागत और कार्य लेखाकार" शब्द के स्थान पर "लागत लेखाकार" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

3-सदस्यों का रजिस्टर

सदस्यों का रजिस्टर अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में रखा जाएगा।

- (iii) विनियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

10. प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र प्रदान करना अथवा अस्वीकार करना

- (1) कोई सदस्य लागत लेखाकार के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार देने वाले प्रमाण पत्र के लिए परिषद में आवेदन कर सकता है।
- (2) प्रैक्टिस प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन उचित प्रपत्र में किया जाएगा तथा उसके साथ वार्षिक प्रमाणपत्र शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क होगा, जब तक कि इसका भुगतान विनियम 7 के अनुसार पहले ही न किया गया हो।
- (3) संस्थान उचित प्रपत्र में प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जो इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत रद्द होने तक वैध होगा।
- (4) सदस्य को प्रैक्टिस बंद करने के बारे में यथाशीघ्र परिषद को सूचित करना होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, प्रैक्टिस बंद करने के दिन से एक माह के बाद नहीं।
- (5) परिषद किसी सदस्य को प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर सकती है, यदि प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र लागू करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत विवरण अपूर्ण, गलत अथवा झूठे पाए जाएं अथवा सदस्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र न हो।
- (iv) विनियम 15ख के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

15ग -सार्वजनिक पटल पर कार्रवाई योग्य सूचना और शिकायतों की स्थिति

- (1) अनुशासनात्मक निदेशालय, बोर्ड और समिति के समक्ष लंबित कार्रवाई योग्य सूचना और शिकायतों की स्थिति संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और उसे प्रति माह अद्यतन किया जाएगा।
- (2) ऐसी लंबित सूचना और शिकायतों की स्थिति में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे: -
 - (i) कार्रवाई योग्य सूचना और लंबित शिकायतों की कुल संख्या।
 - (ii) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के चरण से पहले निदेशालय के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या।
 - (iii) उन मामलों का ब्यौरा जहां प्रारंभिक जांच रिपोर्ट निदेशक (अनुशासन) द्वारा निम्नलिखित को प्रस्तुत की गई है-

क. अनुशासन मंडल

ख. अनुशासनात्मक समिति

(iv) निम्नलिखित के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा (वापस ली गई सुनवाई सहित, यदि कोई हो)

क. अनुशासन मंडल

ख. अनुशासनात्मक समिति

(v) उन मामलों का ब्यौरा जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन निम्नलिखित द्वारा निर्णय सुरक्षित रखे गए हैं:

क. अनुशासन मंडल

ख. अनुशासनात्मक समिति

(vi) उन मामलों का ब्यौरा जहां निर्णय जारी किए गए हैं लेकिन निम्नलिखित द्वारा जिनमें अभी निर्णय दिया जाना है-

क. अनुशासन मंडल

ख. अनुशासनात्मक समिति

(vii) उन मामलों का ब्यौरा जिनमें निम्नलिखित के द्वारा निर्णय दे दिए गए हैं -

क. अनुशासन मंडल

ख. अनुशासनात्मक समिति

(viii) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील मामलों का आंकड़ों के साथ ब्यौरा

क. अपील की अनुमति,

ख. आंशिक रूप से अनुमति,

ग. बर्खास्त

(3) निपटान सांख्यिकी में निपटान का ब्यौरा भी शामिल होगा; अर्थात् ऐसे मामलों की संख्या जिनमें फटकार का दंड, रजिस्टर से हटाने, जुर्माना अथवा रजिस्टर से हटाने और जुर्माना दोनों का दंड दिया गया हो।

(4) निम्नलिखित प्रारूप में सूचना संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी और उसे प्रति माह अद्यतन किया जाएगा। यह सूचना उन सभी फर्मों/लागत लेखाकारों के लिए तैयार की जाएगी जिनके मामले या तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (बीओडी/डीसी/अपीलीय प्राधिकरण/न्यायालय के समक्ष) लंबित हैं या जिनके मामले में, पीईआर वित्तीय वर्ष के दौरान दायर किया गया है:

वित्तीय वर्ष

माह

तक अद्यतन

1. क्रम सं.

2. फर्म का नाम

3. को पीईआर दायर किया गया

4. बीओडी/डीसी के स्तर पर स्थिति - लंबित/निर्णीत

5. बीओडी/डीसी का अंतिम निर्णय - धारा/अनुसूची/दिशानिर्देशों के अंतर्गत दोषी नहीं/दोषी

6. उच्चतर मंच में निर्णय – उच्चतर मंच में दायर कोई मामला नहीं/ ए/डब्ल्यू स्तर के समक्ष दायर मामला

(5) अनुशासन बोर्ड द्वारा धारा 21क की उपधारा (5) और (6) के अंतर्गत और अनुशासन समिति द्वारा उपधारा (5) के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश और

अधिनियम की धारा 21ख के संबंधित पक्षकारों को सूचित किए जाने के बाद प्रत्येक मामले के संबंध में संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) विनियम 15ग के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

15 घ - अधिनियम की धारा 21क और धारा 21ख के अंतर्गत गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति में नामांकन के लिए व्यक्तियों का पैनल

(1) परिषद अधिनियम की धारा 21क और 21ख की उप-धारा (1) के खंड (क) अर्थात् कानून में अनुभव रखने वाले और अनुशासनात्मक मामलों तथा पेशे का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति और (ख) अर्थात् कानून, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वित्त अथवा लेखा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार गठित किए जाने वाले अनुशासन बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए केंद्र सरकार, व्यक्ति (व्यक्तियों) का पैनल तैयार और प्रदान करेगी।

परिषद की खोज समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में, शामिल किए जाने के लिए भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निदेशक (वित्त) से सेवानिवृत्त अधिकारियों, केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारी, जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले समूह 'क' सेवा के अधिकारी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव सहित अपर जिला न्यायाधीश सहित सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को उचित सम्मान दिया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 21क और 21ख की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के तहत अनुशासन बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति में केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के लिए पैनल तैयार करने के उद्देश्य से, परिषद निम्नलिखित कार्य कर सकती है:-

(i) एक खोज-सह-चयन-समिति (जिसे बाद में खोज समिति कहा गया है) का गठन जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा नामित एक परिषद सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले परिषद के नामित सदस्य होंगे। परिषद का अध्यक्ष खोज समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) संस्थान के सचिव इस खोज समिति के सचिव होंगे।

(3) अधिनियम की धारा 21क और 21ख की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए खोज समिति, आवेदन आमंत्रित करेगी, प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और परिषद के विचार के लिए एक पैनल तैयार करेगी:

बशर्ते कि ऐसे पैनल में, अधिनियम की धारा 21क और 21ख की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के अनुसार खोज समिति अपने स्तर पर उचित प्रतिष्ठा वाले और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर सकती है।

बशर्ते कि पैनल में शामिल होने के अनुरोध की तारीख से ठीक दो वर्ष पहले कभी भी संस्थान की सदस्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा जो वर्तमान परिषद अथवा तत्काल पिछली परिषद का सदस्य रहा हो, अधिनियम की धारा 21क और 21ख की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) खंड के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी में पैनल में रखे जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

- (4) खोज समिति, आवेदनों को आमंत्रित करने, उनकी जांच करने, परिषद की मंजूरी के लिए पैनल तैयार करने और पैनल में शामिल करने के लिए अन्य व्यक्तियों की पहचान करने हेतु अपनी प्रक्रिया तय करेगी।
- (5) खोज समिति का निर्णय सर्वसम्मत होगा।
- (6) इस प्रकार तैयार किए गए पैनल को परिषद द्वारा तय किए गए अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा।
- (7) धारा 21क और धारा 21ख की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत परिषद द्वारा अनुशासन बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति में सदस्यों के नामांकन के लिए, इस प्रकार नामित सदस्य संस्थान का सदस्य होगा। तथापि, बीओडी/डीसी में इस प्रकार नामांकित सदस्य बीओडी/डीसी का सदस्य रहने के बाद 04 वर्ष की अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (8) परिषद द्वारा केंद्र सरकार को उपलब्ध कराए जाने वाले पैनल में सामान्यतः प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम पांच नाम शामिल होंगे।
- (9) पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है अथवा अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासनात्मक समिति में परिषद द्वारा नामित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और दो वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।
- (10) कोई भी व्यक्ति पैनल में अपना नाम शामिल करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह निम्नलिखित विकलांगताओं में से किसी से भी पीड़ित है:-
 - (क) वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; अथवा
 - (ख) वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है; अथवा
 - (ग) उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है; अथवा
 - (घ) उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, चाहे वह नैतिक अधमता से जुड़ा हो अथवा अन्यथा; अथवा
 - (ङ) उसे किसी भी पद को धारण करने से अयोग्य ठहराने वाला आदेश किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है
 - (च) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 अथवा लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 अथवा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 21(क) अथवा 21(ख) के तहत एक आदेश अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासन समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कोई दंड लगाते हुए पारित पारित किया गया है।

(vi) विनियम 15घ के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

15ड- अधिनियम की धारा 21क और धारा 21ख के अंतर्गत गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को देय भत्ते।

(1) अनुशासन बोर्ड और अनुशासनात्मक समितियों के पीठासीन अधिकारी और सदस्य बोर्ड अथवा समिति की बैठक तथा संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्तों और यात्रा, आवास और स्थानीय परिवहन के खर्चों की प्रतिपूर्ति के, निम्नलिखित रूप में, जैसी भी स्थिति हो, पात्र होंगे:-

- क. यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद के उपाध्यक्ष की तरह स्वीकार्य होगी।
- ख. दैनिक भत्ता और आवास व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद के उपाध्यक्ष की तरह स्वीकार्य होगी।
- ग. स्थानीय परिवहन

स्थानीय परिवहन कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और यदि यह प्रदान नहीं किया जाता है, तो उन्हें वास्तविक दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी जो परिषद के उपाध्यक्ष को स्वीकार्य दरों से अधिक नहीं होगी।

उप-विनियम (1) में भत्तों के अलावा, पीठासीन अधिकारी और अनुशासन बोर्ड, अनुशासनात्मक समितियों के सदस्य, प्रत्येक दिन के लिए क्रमशः बीस हजार रुपये और अठारह हजार रुपये की दर से बैठक शुल्क के लिए भी पात्र होंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अथवा एक कैलेंडर माह में अधिकतम 2,00,000/- रु. होगी।

(vii) विनियम 95 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

95. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

परिषद अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी।

(viii) विनियम 96 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

96. लेखापरीक्षक-

- (1) परिषद द्वारा एक बार नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक लगातार दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि यदि परिषद ऐसी नियुक्ति को बदलना चाहती है, तो उन्हें सी एंड एजी की सहमति लेनी होगी और सी एंड एजी द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल से अन्य लेखापरीक्षक को नियुक्त करना होगा।
- (2) परिषद लेखापरीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी।
- (3) यदि लेखापरीक्षक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है तो उसे सी एंड एजी द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षकों के नए पैनल से भरा जाएगा।

(ix) विनियम 98 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

98. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य –

- (1) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट हैं और जैसा कि परिषद अथवा समय-समय पर इसकी स्थायी समितियों द्वारा सौंपे जा सकते हैं (बजट, लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखाओं, विनियम, दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं को बनाने से संबंधित अनुमोदन को छोड़कर)।
- (2) अध्यक्ष किसी भी कार्य को परिषद अथवा किसी स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ लाने का निर्देश दे सकता है।

(x) विनियम 98 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

98क. उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट हैं और जिन्हें परिषद अथवा इसकी स्थायी समितियों द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

(xi) विनियम 99 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

99. सचिव की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्या।

परिषद के समग्र नियंत्रण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन, सचिव निम्नलिखित कार्य करेगा:

- (1) संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उसके कार्यालय का प्रभारी होना;
- (2) विनियम 11 के प्रावधानों के अनुसार सहयोगियों और अध्येताओं के प्रैक्टिस प्रमाणपत्रों को रद्द करना;
- (3) परिषद द्वारा अनुमत श्रेणियों के भीतर सदस्यों को अकाउंटेंसी के पेशे के अलावा अन्य व्यवसायों में संलग्न होने की अनुमति देना;
- (4) अधिनियम और इन विनियमों द्वारा अपेक्षित रजिस्ट्रों, दस्तावेजों और प्रपत्रों का रख-रखाव करना;
- (5) संस्थान की समस्त संपत्ति का प्रभारी होना;
- (6) परिषद को देय धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और उसके लिए रसीदें भी जारी करना;
- (7) परिषद अथवा उसकी समितियों द्वारा स्वीकृत सीमा के भीतर राजस्व और पूंजीगत व्यय करना;
- (8) संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों को उचित लेखा बनाए रखना और लेखाबहियां, सूचना आदि पहुंचाना;
- (9) परिषद अथवा उसकी समितियों द्वारा स्वीकृत अन्य सभी भुगतान करना;
- (10) कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देना, उन्हें छुट्टी आदि और अन्य भत्ते देना, और नियमों के अनुसार उनकी वेतन वृद्धि को मंजूरी देना;
- (11) बर्खास्तगी को छोड़कर अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना, जिसके संबंध में परिषद की मंजूरी आवश्यक होगी;
- (12) परीक्षाओं, नामांकन, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने और संबंधित मामलों के लिए इन विनियमों के अंतर्गत प्राप्त शुल्क वापस करना अथवा अंतरित करना;
- (13) प्रशिक्षणार्थी के व्यावहारिक प्रशिक्षण में अधिकतम तीन माह की अवधि तक के किसी भी अंतराल को अपने विवेक पर माफ करना;
- (14) परिषद की ओर से सभी पत्र, दिशानिर्देश, परिपत्र, आदेश, निर्णय और अधिसूचना पर हस्ताक्षर करना और जारी करना;
- (15) वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के भीतर संस्थान की ओर से, जो भी समय-समय पर परिषद अथवा उसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाए, करारों, संविदाओं, डीड्स, दस्तावेजों और वचनबद्धताओं आदि पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना।
- (16) समय-समय पर परिषद अथवा इसकी समितियों द्वारा जैसा अनुमोदित किया जाए, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के भीतर, संस्थान की ओर से न्यायालयों अथवा मंचों अथवा न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में किसी भी नागरिक अथवा आपराधिक अथवा अन्य कार्यवाही के मामलों में आवश्यक कदम उठाना और परिषद की ओर से वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना, परिषद की ओर से न्यायवादियों अथवा अधिवक्ताओं को नियुक्त करना, परिषद की ओर से न्यायालयों आदि में दस्तावेज दायर करना।
- (17) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करना जो उपर्युक्त कर्तव्यों के निष्पादन के लिए संगत और सहायक हैं और आवश्यक हो सकते हैं तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो समय-समय पर परिषद अथवा इसकी समितियों द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।

(18) संस्थान के किसी भी अधिकारी अथवा अधिकारियों को मद (4), (6), (7), (8), (9), (12) और (13) के अंतर्गत किसी भी शक्ति अथवा कर्तव्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन करने के लिए अधिकृत करना, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाए।

(xii) विनियम 104 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

104. सदस्यों की सूची

(1) प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को संस्थान के सदस्यों की सूची अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्षेत्रवार प्रकाशित की जाएगी और संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वास्तविक प्रति समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उस कीमत पर बिक्री के लिए अनुरोध किए जाने पर सदस्य(यों) को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) सदस्यों की सूची में सदस्यों के निम्नलिखित ब्यौरे शामिल हों:

(i) नाम - संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार सदस्य का नाम।

(i) यदि सदस्य एमआरए के अंतर्गत पंजीकृत है:

देश का नाम

विनियामक लेखा निकाय का नाम और पता

(ii) लिंग - पुरुष, महिला और अन्य

(iii) योग्यता - संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार सदस्य की योग्यता

(iv) सदस्यता संख्या -

(v) क्या एसोसिएट है अथवा फेलो है

(vi) एसोसिएट अथवा फेलो के रूप में नामांकन का वर्ष

(vii) क्या प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र है

(viii) व्यावसायिक पता

(ix) विदेश में रहने वाले सदस्य - सदस्य का क्षेत्र और भारत में आवासीय पता।

(x) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई योग्य सूचना अथवा विरुद्ध शिकायत के लंबित होने का ब्यौरा।

(xi) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत इसके विरुद्ध कोई जुर्माना लगाए जाने का ब्यौरा।

(xiii) विनियम 108 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

108क फर्म के पंजीकरण का तरीका और निबंधन एवं शर्तें:

(1) प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखाकार अथवा ऐसे लागत लेखाकारों की एक फर्म अथवा लागत लेखाकारों की बहु-विषयक भागीदारी फर्म, एक व्यापार नाम अथवा फर्म नाम में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले, समय-समय पर परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी व्यापार अथवा फर्म के नाम का प्रयोग करने की अनुमति के लिए परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में परिषद में आवेदन करेगा।

(2) मौजूदा व्यापार अथवा फर्म के नाम का प्रयोग करने की अनुमति अथवा व्यापार अथवा फर्म नाम में संशोधन के लिए, इन नियमों के शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी मौजूदा फर्मों को परिषद में आवेदन करना होगा जो उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान व्यापार/फर्म नाम का प्रयोग करने अथवा विद्यमान फर्म के नाम में कोई संशोधन करने की अनुमति दे सकती है।

(3) परिषद किसी विशेष व्यापार अथवा फर्म के नाम को मंजूरी देने से इंकार कर सकती है यदि -

- (ii) ऐसी फर्म का नाम संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार पहले से पंजीकृत किसी अन्य फर्म के नाम की तरह अथवा समान है; अथवा
 - (iii) वह नाम भारत के भीतर अथवा बाहर किसी भी फर्म द्वारा उपयोग में है; अथवा
 - (iv) यदि उसमें किसी देवी/देवता/देवता का नाम है और जिसका सदस्य(यों) के नाम से कोई संबंध नहीं है; अथवा
 - (v) यदि व्यापार/फर्म का नाम वर्णनात्मक है; अथवा
 - (vi) यदि व्यापार/फर्म के नाम से प्रचार की गंध आती है; अथवा
 - (vii) यदि परिषद की राय में ऐसा नाम अवांछनीय है; अथवा
 - (viii) यदि परिषद के मत में फर्म का पंजीकरण अवांछनीय है।
- (4) लागत लेखाकारों की फर्म व्यापार अथवा फर्म के नाम के अनुमोदन, अथवा प्रैक्टिस शुरू करने अथवा संविधान में परिवर्तन अथवा फर्म अथवा कार्यालय के ब्यौरे में परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, के एक माह के भीतर उस कार्यालय, फर्म अथवा परिवर्तनों के संबंध में, जैसी भी स्थिति हो, उपयुक्त प्रपत्र में उन विवरणों से परिषद को सूचित करेगी।
- (5) जहां दो या दो से अधिक सदस्यों अथवा फर्मों के मामले में एक ही व्यापार अथवा फर्म का नाम विगत में फर्मों के रजिस्टर में पंजीकृत किया गया हो, परिषद सदस्य अथवा फर्म को, जैसी भी स्थिति हो, उसे छोड़कर जिसका नाम फर्म के रजिस्टर में पहले पंजीकृत था, उस तरीके में जिसमें परिषद उपयुक्त माने, नाम में परिवर्तन के लिए निर्देश दे सकती है और सदस्य अथवा फर्म निर्देश जारी होने के छह माह के भीतर परिषद को ऐसे परिवर्तन की सूचना दें।
- (6) परिषद, एक वर्ष के भीतर, पहले से पंजीकृत किसी भी फर्म अथवा व्यापार नाम को वापस ले सकती है और परिषद के निर्देश जारी होने के छह माह के भीतर नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन करने का निर्देश दे सकती है, यदि उसे लगता है कि वह नाम उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अनुसार दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है जो फर्म/व्यापार नाम के अनुमोदन के समय लागू थे।
- (6क) परिषद, किसी भी फर्म के पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर, ऐसे पंजीकरण को वापस ले सकती है, यदि उसे पता चलता है कि पंजीकरण अवांछनीय है;
- (7) कोई भी सदस्य किसी ऐसे व्यापार अथवा फर्म के नाम से प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसके संबंध में निर्देश जारी होने की तारीख से छह माह की समाप्ति के बाद उप-विनियम (5) और (6) के तहत निर्देश जारी किया गया है और परिषद ऐसी फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर से हटा देगी।
- (8) परिषद, अपने विवेक से, उचित मामलों में उप-विनियम (4) के तहत ब्यौरा दायर करने में विलंब को माफ कर सकती है।
- (xiv) विनियम 108क के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

108ख-फर्मों का रजिस्टर

- (1) परिषद उचित रूप में फर्मों का एक रजिस्टर अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में बनाएगी और उसमें निम्नलिखित ब्यौरा दर्ज करेगी-

- (i) वे व्यौरे, जो फर्म द्वारा विनियम 108क के तहत प्रस्तुत किए गए हैं।
- (ii) किसी कार्रवाई योग्य सूचना अथवा शिकायत के लंबित होने, अधिनियम के अध्याय V के तहत फर्म के विरुद्ध जुर्माना लगाए जाने का व्यौरा।
- (iii) अधिनियम के अध्याय V के तहत फर्म के विरुद्ध कोई भी जुर्माना लगाए जाने का व्यौरा।
- (iv) अपीलीय प्राधिकारी अथवा किसी न्यायालय के समक्ष दंड से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लंबित होने का व्यौरा;
- (v) उपर्युक्त खंड (ii), (iii) और (iv) के संबंध में, रजिस्टर में प्रविष्टि 60 दिनों के भीतर अद्यतन की जाएगी।

(2) परिषद उस फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर से हटा देगी जो अधिनियम की धारा 20ग के तहत किसी भी अयोग्यता के अधीन है।

- (xv) विनियम 108 ख के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

108ग फर्मों की सूची

- (1) प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार संस्थान की फर्मों की सूची क्षेत्र-वार प्रकाशित की जाएगी और संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। फर्मों की सूची की वास्तविक प्रति ऐसे सदस्य अथवा फर्म को प्रदान की जा सकती है, जिनसे अनुरोध ऐसी कीमत पर प्राप्त हुआ है जो परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।
- (2) फर्मों की सूची दो खंडों में होगी, अर्थात्, स्वामित्व वाली फर्में और भागीदारी फर्में (सीमित देयता भागीदारी सहित) और इसमें फर्मों के निम्नलिखित व्यौरे शामिल होंगे:-

(क) स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में

- (i) फर्म का नाम
- (ii) फर्म की पंजीकरण संख्या
- (iii) स्वामी का नाम (सदस्य)
- (iv) सदस्यता संख्या
- (v) सदस्य का सीओपी स्तर
- (vi) फर्म का पूरा पता
- (vii) किसी अन्य फर्म में सदस्य संघ
- (viii) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई योग्य किसी भी सूचना अथवा शिकायत के लंबित होने का व्यौरा।
- (ix) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई जुर्माना लगाए जाने का व्यौरा।
- (x) कोई अन्य व्यौरा जो समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) भागीदारी फर्मों के मामले में

- (i) फर्म का नाम
- (ii) फर्म की पंजीकरण संख्या

- (iii) भागीदार का नाम
- (iv) भागीदारों की सदस्यता संख्या
- (v) भागीदारों का सीओपी स्तर
- (vi) किसी अन्य फर्म में भागीदार एसोसिएशन
- (vii) प्रधान कार्यालय का पता
- (viii) शाखा (शाखाओं) की संख्या
- (ix) शाखा कार्यालय (कार्यालयों) का पता
- (x) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई योग्य किसी भी सूचना अथवा शिकायत के लंबित होने का ब्यौरा।
- (xi) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई जुर्माना लगाए जाने का ब्यौरा।
- (xii) कोई अन्य ब्यौरा जो समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (xvi) विनियम 133 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

133. लेखापरीक्षा-

- (1) क्षेत्रीय परिषद के लेखाओं की प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल से परिषद द्वारा नियुक्त उसी फर्म द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।
- (2) लेखापरीक्षा रिपोर्ट और क्षेत्रीय परिषद की रिपोर्ट के साथ लेखे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले संबंधित क्षेत्रों में सदस्यों को भेजे जाएंगे और निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक आम बैठक से पहले अपनाए जाने के लिए रखे जाएंगे।
- (3) यदि किसी लेखापरीक्षक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल में से परिषद द्वारा नियुक्त उसी फर्म को नियुक्त किया जा सकता है।

कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./316/2023-24]

अनुसूची-'क'

उपयुक्त प्रपत्र

प्रपत्र "1"

(विनियम 3 के साथ पठित धारा 19(1) और (2) देखें)

सदस्यों का रजिस्टर

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

- 1. सदस्यता संख्या
- 2. पूरा नाम
- 3. जन्मतिथि
- 4. मूल निवास
- 5. आवासीय पता
- 6. व्यावसायिक पता

7. रजिस्टर में प्रविष्टि की तिथि
8. योग्यताएँ
9. क्या आपके पास प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र है
10. फेलो के रूप में प्रवेश की तिथि
11. क्या स्वतंत्र रूप से, भागीदारी में प्रैक्टिस कर रहे हों अथवा प्रैक्टिस में लागत लेखाकारों की किसी फर्म में कार्यरत हैं
12. क्या वेतनभोगी रोजगार है, यदि प्रैक्टिस में नहीं है
13. पते में परिवर्तन, यदि कोई हो
14. अध्याय V के अंतर्गत कार्रवाई योग्य शिकायत अथवा लंबित सूचना अथवा उसके विरुद्ध लगाए गए किसी जुर्माने का ब्यौरा सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:
सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई योग्य शिकायतों/सूचना का ब्यौरा#:-

शिकायत/ सूचना संदर्भ संख्या	यदि शिकायत/ सूचना कार्रवाई योग्य है	अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासनात्मक समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित सूचना अथवा शिकायत का ब्यौरा	यदि जांच के बाद अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासनात्मक समिति द्वारा पेशेवर अथवा अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ लगाए गए दंड का ब्यौरा	यदि बीओडी अथवा डीसी द्वारा पेशेवर अथवा अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ उसका ब्यौरा	यदि जुर्माना लगाया गया है, तो अपीलीय प्राधिकारी/उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामले का ब्यौरा, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(प्रत्येक शिकायत/सूचना के लिए अलग पंक्ति का उपयोग किया जाए)

15. अभ्युक्तियां

प्रपत्र "1क"
(अधिनियम की धारा 108ख के साथ पठित विनियम 20ख देखें)

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की फर्मों का रजिस्टर

1. फर्म की पंजीकरण संख्या
2. फर्म का नाम
3. गठन की तिथि
4. फर्म का प्रकार - मालिकाना/भागीदारी/एलएलपी/एमडीपी
5. फर्म के नाम के अनुमोदन की तिथि
6. प्रधान कार्यालय का पता
7. भागीदारों का ब्यौरा (उनके शामिल होने और छोड़ने की तिथि सहित)
8. फर्म के शाखा कार्यालय- उनके पते, खोलने, बंद करने की तारीख और प्रभार ब्यौरे के साथ
9. फर्म का दूसरा कार्यालय
10. वेतनभोगी सहायकों का ब्यौरा, उनके शामिल होने और छोड़ने की तारीख के साथ
11. फर्म का पैना
12. फर्म का जीएसटीआईएन
13. फर्म और भागीदारों का संपर्क नंबर और ईमेल आईडी
14. दिनांक एवं फर्म संख्या सहित विलय एवं पृथक्करण का ब्यौरा
15. भागीदारों का अन्य संघ
16. फर्म के नेटवर्क का ब्यौरा
17. भागीदारों के बीच विवाद का ब्यौरा, यदि कोई हो।
18. क्या अध्याय V के अंतर्गत फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई योग्य सूचना अथवा शिकायत लंबित है अथवा जुर्माना लगाया गया है, यदि कोई हो, सारणीबद्ध रूप में # जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

शिकायत/ सूचना संदर्भ संख्या	यदि शिकायत/ सूचना कार्रवाई योग्य है	अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासनात्मक समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित सूचना अथवा शिकायत का ब्यौरा	यदि जांच के बाद अनुशासन बोर्ड अथवा अनुशासनात्मक समिति द्वारा पेशेवर अथवा अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ लगाए गए दंड का ब्यौरा	यदि बीओडी अथवा डीसी द्वारा पेशेवर अथवा अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ उसका ब्यौरा	यदि जुर्माना लगाया गया है, तो अपीलीय प्राधिकारी/उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामले का ब्यौरा, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रत्येक शिकायत/सूचना के लिए अलग पंक्ति का उपयोग किया जाए

19. अभ्युक्तियां

टिप्पणी:-मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 मई, 1959 में अधिसूचना संख्या 10(13) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। आईएनएस/59 दिनांक 25 मई, 1959 और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2014 दिनांक 12 नवंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**(Statutory Body under an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 1st August, 2023

CWR(1)/2023.—The following draft of Regulations to further amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, which the Council of the Institute of Cost Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) for the information of all stakeholders likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published, are made available to the public.

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft Regulations, may forward the same for consideration by the Council of the Institute of Cost Accountants of India within the period so specified addressed to the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016.

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft Regulations before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulation may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2023
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959
 - (i) In Regulation 1 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the words “Cost and Works Accountants” the words “Cost Accountants” shall be substituted.
 - (ii) For Regulation 3, the following shall be substituted, namely:

“3 – Register of Members

The Register of Members shall be maintained in the appropriate Form referred to in Schedule ‘A’

- (iii) For Regulation 10, the following shall be substituted, namely:

“10- Grant or refusal of Certificate of Practice

- (1) A member may apply to the Council for a certificate entitling him to practise as a cost accountant.
- (2) An application for the grant of certificate of practice shall be made in the appropriate Form and shall be accompanied by the annual certificate fee and the annual membership fee unless the same has already been paid in accordance with Regulation 7.
- (3) The Institute may issue the Certificate of Practice in the appropriate Form which shall be valid until it is cancelled under the provisions of these Regulations.
- (4) On his ceasing to be in practice, a member shall inform the Council as soon as may be, but in any case, not later than one month from the day he ceases to practice.
- (5) The Council may refuse to grant Certificate of Practice to a Member, if the particulars furnished in prescribed form for applying Certificate of Practice are found to be incomplete, incorrect or false or the member is not eligible to obtain such certificate under other provisions of the Act.

- (iv) After Regulation 15B, the following regulations shall be inserted, namely:

“15C-Status of actionable information and complaints in public domain

- (1) The status of actionable information and complaints pending before the Disciplinary Directorate, the Board and the Committee shall be made available on the website of the Institute and shall be updated every month.
- (2) The status of such pending information and complaints shall contain the following details:-
 - (i) Total number of actionable information and complaints pending.
 - (ii) Number of cases which are pending for investigation before the Directorate prior to the stage of preliminary examination report.

- (iii) Break up of cases where Preliminary Examination Report has been submitted by Director (Discipline) to the—
 - a. Board of Discipline
 - b. Disciplinary Committee
- (iv) Break-up of cases pending for hearing (including recalled hearings, if any) before the—
 - a. Board of Discipline
 - b. Disciplinary Committee
- (v) Break up of cases where hearing has been concluded but findings have been kept reserved by the:
 - a. Board of Discipline
 - b. Disciplinary Committee.
- (vi) Break-up of cases where findings have been issued but punishments are yet to be awarded by the –
 - a. Board of Discipline.
 - b. Disciplinary Committee.
- (vii) Break-up of cases in which punishments have been awarded by the –
 - a. Board of Discipline.
 - b. Disciplinary Committee.
- (viii) Break-up of appeal cases filed before Appellate Authority with statistics of
 - a. Appeals allowed,
 - b. Partly allowed,
 - c. Dismissed.
- (3) Disposal Statistics to also include break-up of disposal i.e.; number of cases in which penalty of reprimand, removal from the register, fine or both removal from the register and fine, have been awarded.
- (4) Information in the following format shall also be displayed on the website of the Institute and will be updated every month. This information shall be prepared for all firms/Cost Accountants whose cases are either pending at the beginning of the financial year (before BoD/DC/Appellate Authority/Court) or in whose case, the PER has been filed during the financial year:

Financial Year _____ Updated upto month _____

 1. Sl. No.
 2. Name of the Firm
 3. PER filed on
 4. Status at BoD/DC - Pending/ Decided
 5. Final Decision of BoD/DC - Not Guilty/Guilty under Section___/Schedule___/Guidelines __
 6. Decision in Higher Forum - No case filed in Higher Forum/ Case filed before ____ a/w Status
- (5) The final Order passed by the Board of Discipline under sub-section (5) and (6) of Section 21A and by the Disciplinary Committee under sub-section (5) and (6) of Section 21B of the Act shall be made available on the website of the Institute in respect of each case after the same is communicated to the parties concerned.
 - (v) After Regulation 15C, the following regulations shall be inserted, namely:

“15D Panel of persons for nomination to the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act

(1)The Council shall prepare and provide to the Central Government, Panel(s) of persons for nomination of the Presiding Officer and other members of the Board of Discipline and the Disciplinary Committee to be constituted as per the eligibility criteria laid down under clause (a) i.e. persons with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession and (b) i.e. persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy, of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.

Due regard shall be given to Officers retired from Indian Revenue Service, Indian Corporate Law Service, Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian P&T

Accounts & Finance Service, Indian Railway Accounts Service, Director (Finance) of PSUs, Officers of Central/State Govts. as may be notified by Central Government, having 20 years of Group “A” service experience, Retired High Court Judge, Retired District Judge including Addl. District Judge with minimum five years of experience as District Judge or Addl. District Judge, for inclusion in the panel prepared by the Search Committee of the Council.

(2) For the purpose of preparing the Panel(s) for Presiding Officer and members to be nominated by the Central Government to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, the Council may:-

- (i) constitute a Search-cum-Selection Committee (hereinafter referred to as the Search Committee) consisting of President, Vice President, a Council Member to be nominated by the President and two Govt. Nominated Members of the Council to be nominated by the Central Government. The President of the Council shall be the Chairperson of the Search Committee.
 - (ii) Secretary of the Institute shall be the Secretary to this Search Committee.
- (3) Search Committee for the purpose of clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, shall invite applications, scrutinize the applications received and prepare a panel for consideration of the Council:

Provided that in such panel, the Search Committee at its own may also include the names of persons of appropriate standing and having qualification as per clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.

Provided further that no person holding membership of the Institute anytime immediately preceding two years from date of request for empanelment or who has been a member of the current Council or the immediate previous Council, shall be eligible for empanelment in the category of persons mentioned under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.

- (4) The Search Committee, for the purpose of inviting, scrutiny of applications, preparation of panel for approval of the Council and identifying other persons for inclusion in the Panel shall decide its own procedure.
- (5) The decision of the Search Committee shall be unanimous.
- (6) The Panel so prepared shall be updated at such interval as may be decided by the Council.
- (7) For nomination of members by the Council to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (c) of sub-section (1) of Section 21A and of Section 21B, the member so nominated shall be a member of the Institute. However, the member so nominated in the BoD/DC shall not be eligible to contest election for a period of 04 years after he/she ceases to be member of BoD/DC.
- (8) The Panel to be provided by the Council to the Central Government shall include at least five names for each vacancy ordinarily.
- (9) Presiding Officer or member(s) who have been nominated by the Central Government or member(s) nominated by the Council to Board of Discipline or Disciplinary Committee, shall hold office for period of two years and shall be eligible for being considered for one more term of two years
- (10) No person shall be eligible for inclusion of his name in the panel, if he suffers from any of the following disabilities: -
 - (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (b) he is an undischarged insolvent; or
 - (c) he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending; or
 - (d) he has been convicted by a Court of an offence, whether involving moral turpitude or otherwise; or
 - (e) an order disqualifying him from holding any post has been passed by a Court or tribunal or
 - (f) an order under Section 21(A) or 21(B) of the Chartered Accountants Act, 1949 or the Cost and Works Accountants Act, 1959 or the Company Secretaries Act, 1980 has been passed imposing any punishment by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee, as the case may be.

- (vi) After Regulation 15D, the following regulations shall be inserted, namely:

15E -Allowances payable to the Presiding Officer and members of the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act.

- (1) The Presiding Officer and the Members of the Boards of Discipline and the Disciplinary Committees shall be eligible for daily allowances and reimbursement of expenses of travelling, lodging and local conveyance for attending the meeting and related functions of the Board or the Committee, as the case may be, as follows: -
- Reimbursement of travelling expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council.
 - Daily allowance and reimbursement of lodging expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council.
 - Local Conveyance

The local conveyance shall be provided by the office and in case the same is not provided, they will be reimbursed as per actuals not exceeding the rates admissible to the Vice President of the Council.

In addition to the allowances at sub-regulation (1), the Presiding Officers and the members of the Boards of Discipline, Disciplinary Committees, shall also be eligible for sitting fees @ Rupees Twenty thousand and Rupees Eighteen thousand respectively for each day, subject to a maximum of Rs.2,00,000/- in a calendar month or as modified by Central Government from time to time.

- (vii) For Regulation 95, the following shall be substituted, namely:

“95- Appointment of auditors

The Council shall appoint a firm of chartered accountants as auditor every year in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 18 of the Act.

- (viii) For Regulation 96, the following shall be substituted, namely:

“ 96- Auditors

- The auditors once appointed by Council shall be eligible for re-appointment for two more consecutive years provided if the Council wants to change such appointment, they shall seek the consent of C&AG and appoint another auditor from the panel of auditors maintained by C&AG.
- The Council shall determine remuneration to be paid to the auditors.
- If any vacancy occurs in the office of an auditor the same shall be filled up from the fresh panel of auditors maintained by C&AG.

- (ix) For Regulation 98, the following shall be substituted, namely:

“98- Powers and duties of the President

- The President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council (except for approval related to Budget, Audited Annual Financial Accounts, powers to make regulations, guidelines and procedures) or its Standing Committees from time to time.
- The President may direct any business to be brought before the Council or any Standing Committee for consideration.

- (x) After Regulation 98, the following regulations shall be inserted, namely:

“98A- Powers and duties of the Vice-President

The Vice-President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council or its Standing Committees from time to time.

- (xi) For Regulation 99, the following shall be substituted, namely:

“ 99- Powers, duties and functions of the Secretary.

Subject to the overall control, guidance and supervision of the Council, the Secretary shall execute the following functions:

- being in charge of the office of the Institute as its Chief Executive Officer;
- cancelling of certificates of practice of associates and fellows in accordance with the provisions of Regulation 11
- granting of permission to members to be engaged in other occupations besides the practice of the profession of accountancy within the categories permitted by the Council;
- maintaining registers, documents and forms as required by the Act and these Regulations;
- being in charge of all the property of the Institute;

- (6) making necessary arrangements for receiving moneys due to the Council and also issuing receipts therefor;
- (7) incurring revenue and capital expenditure within the limits sanctioned by the Council or its Committees;
- (8) causing proper accounts to be maintained and delivering of account books, information etc. to the auditors appointed by the Council for the purpose of audit of accounts of the Institute;
- (9) making all other payments as sanctioned by the Council or its Committees;
- (10) paying salary and allowances to the staff, granting of leave etc. to them, and other perks to them, and sanctioning their increments in accordance with the regulations;
- (11) exercising disciplinary control over the officers and employees except dismissal in respect of which the sanction of the Council shall be necessary;
- (12) refunding or transferring fees received under these Regulations for the examinations, enrolment, issue of certificate of practice and allied matters;
- (13) condoning any break in the practical training of the trainee up to a maximum period of three months in his discretion;
- (14) signing and issuing all communications, guidelines, circulars, orders, decisions and notifications on behalf of the Council;
- (15) signing and execution of agreements, contracts, deeds, documents and undertaking, etc., on behalf of the Institute within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time.
- (16) taking necessary steps in matters of any civil or criminal or other proceeding on behalf of the Institute in courts or forums or judicial or quasi-judicial authorities and signing vakalatnamas on behalf of the Council, appointing solicitors or advocates on behalf of the Council, and filing papers in Courts, etc. on behalf of the Council, within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time;
- (17) performing such other duties and functions as are incidental and ancillary to and may be required for the performance of the above duties and exercising such other powers as may be delegated by the Council or its Committees from time to time.
- (18) authorizing any officer or officers of the Institute to exercise or discharge any powers or duties under items (4), (6), (7), (8), (9), (12) and (13) as may be considered necessary from time to time.

(xii) For Regulation 104, the following shall be substituted, namely:

“104 - List of Members

- (1) The list of members of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise, under sub-section (3) of section 19 of the Act and shall be made available at the website of the Institute. Physical copy shall be made available to member(s) on request, for sale at such price as may be fixed by the Council from time to time.
- (2) The list of Members may contain the following details of members:
 - (i) Name – Member’s Name as per records of the Institute.
 - (ia) In case the member is registered under MRA:

Name of the Country

Name & address of the Regulating Accounting Body
 - (ii) Gender – Male, Female and Others
 - (iii) Qualification – Member’s qualification as per records of the Institute
 - (iv) Membership No. -
 - (v) Whether Associate or Fellow
 - (vi) Year of enrolment as Associate or Fellow
 - (vii) Whether holding Certificate of Practice
 - (viii) Professional Address
 - (ix) Members residing abroad - Member’s Region and residential address in India.
 - (x) Details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.

(xi) Details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.

(xiii) After Regulation 108, the following regulations shall be inserted, namely:

“108A - Manner of registration of firm and terms and conditions:

- (1) A cost accountant in practice or a firm of such cost accountants or Multi-Disciplinary Partnership firm of Cost Accountants, shall, before commencement of practice in a trade name or firm name, apply to the Council in the form approved by the Council for permission to use a trade or a firm name as per the guidelines issued by the Council from time to time.
- (2) For permission to use the existing trade or firm name or modification in trade or firm name, all the existing firms within 30 days from the date of commencement of these regulations, shall apply to the Council which may allow use of the existing trade/firm name or any modification in the name of the existing Firm as per the guidelines issued under sub-regulation (1) above
- (3) The Council may, refuse to approve a particular trade or firm name if –
 - (i) the name of such firm is identical or similar to the name of any other firm already registered as per the records of the Institute; or
 - (ii) the name is in use by any firm within or outside India; or
 - (iii) If it bears the name of a god/goddess/deity and which has no relationship with the name of member(s); or
 - (iv) if the trade/firm name is descriptive; or
 - (v) if the trade/firm name smacks of publicity; or
 - (vi) if such name, in the opinion of the Council is undesirable; or
 - (vii) if in the opinion of the Council, the registration of the firm is undesirable.
- (4) The firm of cost accountants shall within one month of the approval of the trade or firm name, or commencement of practice or change in the constitution or change in particulars of the firm or office, as the case may be, inform the Council of such particulars regarding his office, firm and changes as the case may be, in the appropriate Form.
- (5) Where the same trade or firm name has been registered in the past in the register of firms in the case of two or more members or firms, the Council may direct the member or the firm, as the case may be, other than one whose name was registered first in the register of firms, to alter the name in such manner as the Council may consider appropriate and member or firms inform to the Council of such alteration within six months of the issue of the direction.
- (6) The Council may recall, within one year, any Firm or trade name already registered and may direct to apply for a change in the name within six months from the issuance of directions of the Council, in case it finds the name earlier approved was not in accordance with the guidelines as per above sub-Regulation (1) which were in force at the time of approval of firm / trade name.
- (6A) The Council may recall, within one year of registration of any firm, such registration in case it finds that the registration is undesirable;
- (7) No member shall practice under a trade or firm name in respect of which a direction has been issued under sub-regulation (5) & (6) after the expiry of six months from the date of issue of the direction and the Council shall remove the name of such firm from the register of firms.
- (8) The Council may, in its discretion, condone the delay in filing the particulars under sub-regulation (4) in appropriate cases.

(xiv) After Regulation 108A, the following regulations shall be inserted, namely:

“108B -Register of Firms

- (1) The Council shall maintain a register of firms in appropriate form referred to in Schedule ‘A’ and shall enter therein the following details-
 - (i) particulars which are furnished by the firm under Regulation 108A
 - (ii) details of pendency of any actionable information or complaint, imposition of penalty against the Firm under Chapter V of the Act.
 - (iii) details of imposition of any penalty against the Firm under Chapter V of the Act.
 - (iv) details of pendency of any legal proceedings related to penalty in the Appellate Authority or before any Court;
 - (v) In respect of clauses (ii), (iii) and (iv) above, the entry in the Register shall be updated within 60 days.
- (2) The Council shall remove the name of a firm from the Register of Firms which is subject to any of the disabilities under **section 20C of the Act.**

(xv) After Regulation 108B, the following regulations shall be inserted, namely:

“108C- List of Firms

- (1) The List of Firms of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise and shall be made available at the website of the Institute. Physical copy of the list of firms may be provided to such member or firm from which a request has been received at such price as may be fixed by the Council from time to time.
- (2) The list of Firms shall be in two segments i.e., proprietorship firms and partnership firms (including Limited Liability Partnership) and may contain the following details of firms:-

(a) In the case of Proprietorship Firms

- (i) Firm Name
- (ii) Firm Registration Number
- (iii) Proprietor Name (Member)
- (iv) Membership No.
- (v) COP Status of the Member
- (vi) Firm Complete address
- (vii) Member's Association in any other Firm
- (viii) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.
- (ix) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.
- (x) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.

(b) in the case of **Partnership Firms:**

- (i) Firm Name
- (ii) Firm Registration Number
- (iii) Partner Names
- (iv) Membership No. of Partners
- (v) Partners COP Status
- (vi) Partners' Association in any other Firm
- (vii) Address of Head Office
- (viii) Number of Branch(es)
- (ix) Address of Branch Office(s)
- (x) Details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.
- (xi) Details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.
- (xii) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.

(xvi) For Regulation 133, the following shall be substituted, namely:

“133- Audit

- (1) The accounts of a Regional Council, shall be audited every year by the same firm appointed by the Council from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor General of India.
- (2) The accounts together with the audit report and the report of the Regional Council shall be sent to the members in the respective regions at least 14 days before the date of the Annual General Meeting of the Regional Constituency and shall be placed for adoption before the Annual General Meeting of the Constituency.
- (3) If any vacancy occurs in the office of an auditor the same firm appointed by the Council from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor General of India may be appointed.

KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./316/2023-24]

SCHEDULE 'A'

Appropriate Forms
Form "1"
(See Section 19 (1) & (2) read with Regulation 3)
Register of Members
The Institute of Cost Accountants of India

1. Membership Number
2. Name in full
3. Date of Birth
4. Domicile
5. Residential address
6. Professional address
7. Date of entry in the Register
8. Qualifications
9. Whether holding a certificate of practice
10. Date of admission as Fellow
11. Whether practicing independently, in partnership or employed in a firm of Cost Accountants in practice
12. Whether holding a salaried employment, if not in practice
13. Change of address, if any
14. The details of actionable complaint or information pending or any penalty has been imposed against him under Chapter V in the tabular form# as indicated below:

Details of actionable complaints/information against the member#:-

Complaint/ Information Reference No.	If complaint/ Information actionable	Details of information or complaint pending for inquiry before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee	If found guilty of professional or other misconduct by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee after the inquiry, details of penalty imposed along with Order Number	If not found guilty of professional or other misconduct by BoD or DC, the details thereof along with Order Number	If penalty imposed, details of case filed before the Appellate Authority/Higher Court, if any .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Separate row to be used for each complaint/ information)

15. Remarks

Form "1A"**(See Regulation 108B read with Section 20B of the Act)****Register of Firms of the Institute of Cost Accountants of India**

1. Firm Registration Number
2. Firm Name
3. Date of Constitution
4. Type of Firm – Proprietary/Partnership/LLP/MDP
5. Date of approval of Firm Name
6. Address of the Head Office
7. Details of Partners (Along with their date of joining and leaving)
8. Branch office(s) of the firm- along with their address, date of opening, closure and in-charge details
9. Second Office(s) of the Firm
10. Details of Paid Assistants along with their date of joining and leaving
11. PAN of the Firm
12. GSTIN of the firm
13. Contact Number and email ID of the firm and Partners
14. Details of Merger and Demerger along with dates and firm numbers
15. Other association of the partners
16. Details of Network of the Firm
17. Details of dispute among the partners, if any.
18. Whether any actionable information or complaint is pending or penalty imposed, if any, against the firm under Chapter V in the tabular form# as indicated below:

Complaint/ Information Reference No.	If complaint/ Information actionable	Details of information or complaint pending for inquiry before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee	If found guilty of professional or other misconduct by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee after the inquiry, details of penalty imposed along with Order Number	If not found guilty of professional or other misconduct by BoD or DC, the details thereof along with Order Number	If penalty imposed, details of case filed before the Appellate Authority/Higher Court, if any .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Separate row to be used for each complaint/ information

19. Remarks

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th May, 1959 vide Notification No. 10 (13). Ins/59 dated 25th May, 1959 and lastly amended vide Notification No. CWR (1) 2014 dated 12th November, 2014.